uon before the construction work is taken up. Neither the details of the revision nor the date of starting the work can be anticipated for the present .

(d) The information is being collected and will be laid on the Table of the Sabha.

Scheme for providing drinking water in Rajasthan

7250. SHRI RAMDAS AGARWAL: Will the Minister of URBAN DEVELOPMENT be pleased to state;

(a) what headway has been made so far in finalising schemes to arrange water for drinking purposes in such areas of Rajasthan where its scarcity is being felt;

(b) whether any specific request has been received from the Government of Rajasthan and if so, the details thereof; and

(c) whether any funds allocated in 1994-95 for such purposes to the Government of Rajasthan?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT (SHRI P. K. THUN. GON): (a) to (c) The information is being collected and will be laid on the Table of the Sabha.

मध्य प्रदेश के शहरों में पर्यावरण सुधार कार्य हेतु प्रस्ताव

7251. **श्री गोविन्द राम मिरी** : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश सरकार की ओर से ब्रिटिश सरकार (ओ डी ए) की सहायता से हैबिटेंट इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट के अंतर्गत मध्य प्रदेश के छः शहरों अर्थात भोपाल ग्वालियर, जबलपुर, दुर्ग, सागर और रायपुर में पर्यावरण सुधार कार्य सम्बन्धी कोई प्रस्ताव केन्द्र सरकार के पास स्वीकृति हेतु लम्बित है और

(ख) यदि हां, तो उसे कब तक स्वीकृति प्रदान कर दी जाएगी ;

(ग) क्या शहरी गरीबों के लिए मूलभत सुख-सुविधाएं उपलब्ध कराने सम्बन्धी कार्यक्रम के अन्तर्गत मध्य प्रदेश के ग्यारह (11) नगरों अथात् ग्वालियर, दुर्ग, उज्जैन, बिलासपुर, रीवां, सतना, रतलाम, रायपुर, सागर, देवास और नरसिंहपुर के सम्बध में कोई प्रस्ताव केन्द्र सरकार के पास स्वीकृति हेतु लम्बित है ; और

(घ) यदि हां, तो उसे कब तक स्वीकृति प्रदान कर दी जाएगी ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. के. थुंगन) : (क) पर्यावास सुधार परियोजना के तहत ओ.डी.ए. की सहायता से मध्य प्रदेश के छः शहरों (भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर, दुर्ग, सागर और रायपुर) में पर्यावरण सुधार के लिए मध्य प्रदेश सरकार का कोई प्रस्ताव इस मंत्रालय में लम्बित नहीं है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) जी, नहीं। मध्य प्रदेश के बारह शहरों में शहरी लोगों को बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने सम्बन्धी मध्य प्रदेश सरकार का कोई प्रस्ताव इस मंत्रालय में लम्बित नहीं है। तथापि, गरीबों के लिए शहरी बुनियादी सेवाओं की केन्द्र प्रवर्तित योजना मध्य प्रदेश के दस शहरों अर्थात, बरसिया, कटनी, रायगढ़, चासिया, रजनूद गांव, मंदसौर, गुरहानपुर, भोपाल, जबलपुर और खंडवा में कार्यान्वित की जा रही है।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

Allotment of Government residential accommodation on ad-hoc basis

7252. PROF. VIJAYA KUAMR MALHOTRA; Will the Minister of URBAN DEVELOPMENT be pleased to state

(a) whether it is a fact that government residential accommodation, have been allotted on large scale on ad-hoc basis in the preceeding three years;